भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4273
उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2026

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में भारतनेट का कार्यान्वयन और दूरसंचार कनेक्टिविटी

4273. श्री राजीव रायः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024-26 के दौरान भारतनेट परियोजना के अंतर्गत मऊ जिले में घोसी निर्वाचन क्षेत्र सहित कितनी ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार और कार्यशील बनाया गया है;

(ख) उक्त जिले में 4जी और 5जी मोबाइल नेटवर्क कवरेज की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश में भारतनेट और अन्य ग्रामीण दूरसंचार पहलों के अंतर्गत जारी की गई कुल निधि और मऊ जिले में किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी समीक्षा में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा घोसी में डिजिटल पहुंच और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) घोसी निर्वाचन क्षेत्र सहित मऊ जिले में, वर्ष 2024-26 की अवधि के दौरान भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 596 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

(ख) मऊ जिले के सभी गांवों को 4जी/5जी मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर कर लिया गया है। इस जिले में दिनांक 28.02.2026 तक 2,544 4जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) और 596 5जी बीटीएस शुरू किए जा चुके हैं।

(ग) मऊ जिले सहित उत्तर प्रदेश राज्य में दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि से दिनांक 28.02.2026 तक, भारतनेट के अंतर्गत 6,638.56 करोड़ रुपये और अन्य मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के अंतर्गत 1,184.17 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के घोसी निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल पहुंच को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) बेहतर विश्वसनीयता के लिए रिंग आर्किटेक्चर में भारतनेट नेटवर्क का सृजन और उन्नयन;

(ii) 10 वर्षों के लिए नेटवर्क का प्रचालन और रखरखाव;

(iii) एक समर्पित नेटवर्क प्रचालन केंद्र (एनओसी) की संस्थापना; और

(iv) 1.5 करोड़ एफटीटीएच कनेक्शनों का प्रावधान।

*****